राष्ट्रीय सहारा



मयंक शेखर

23-3-2001

# चीन से मोह अब भी नहीं टूटा

नेपाल नरेश वीरेन्द्र का चीन की पांच दिवसीय यात्रा पर जाना ऐसे समय में मायने रखता है जब नेपाल में सक्रिय चीन समर्थित माओवादी कम्युनिस्ट गुट (एमसीसी) और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गठजोड़ को भारत विरोधी गतिविधियां पूरे उफान पर हैं। इस यात्रा की तैयारी के सिलसिले में 21 फरवरी को चीन के रक्षामंत्री जनरल चि हौतियन काठमांडो पहुंचे और दो दिनों तक उनकी नेपाल के रक्षामंत्री महेश आचार्य से कई दौर की बातचीत होती रही। बातचीत का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया।

भारत में जो समाचार पहुंचा उससे तो यह जाहिर होता है कि बातचीत में सिर्फ नरेश वीरेन्द्र के बीजिंग दौरे से संबंधित मुद्दे थे और 26 फरवरी को वाकई वीरेन्द्र चीन पहुंच भी गये। लेकिन इस बात की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हथियारों की खरीद के बारे में भी कुछ बातें हुई हैं।

1988 में भी नेपाल ने चीन से बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे हथियार खरीदे, जिसका पता आखिरकार भारत को चल गया और भारत ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की। क्योंकि उन हथियारों में विमान भेदी तोपें तथा बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं।

दिसम्बर 1999 में काठमांडो के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आईएसआई द्वारा तैयार की गयी योजना के तहत भारतीय विमान के अपहरण के बाद जो भारत-नेपाल संबंध में खटास पैदा हुई उसे मधुर करने के प्रयास में पिछले वर्ष जून में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत आये। हालांकि सफलता उन्हें आंशिक रूप से ही मिली, लेकिन ऐसा लगा मानो माहौल बदल रहा है, लेकिन तब तक 2001 शुरू होते-होते ऋतिक रोशन वाली घटना हो गयी जिससे जितने देर से गाड़ी पटरी पर आयी थी उतनी जल्दी में उतर गयी। ऋतिक रोशन वाले मामले को उछालने की साजिश भी भारत विरोधी गतिविधियों का एक हिस्सा था, क्योंकि जिस टीवी यूनिट ने पहली बार यह मामला उछाला उसका संचालक एक पाकिस्तानी निकला और वो उस घटना के बाद ही लापता हो गया। भारत का नेपाल से सहज रूप में रिश्ता बनता है। इसलिए उस स्थिति में भारत की चिंता स्वाभाविक है जब नेपाल ऐसे देशों को अपना हितैषी माने जो भारत के प्रतिद्वंद्वी हैं।

खासकर चीन से नजदीकी तो और भी मायने रखती है, क्योंकि भारत को हमेशा इससे खतरा बना रहता है। पाकिस्तान तो बहरहाल इन दिनों लगातार इस कोशिश में जुटा है कि भारत के अंदर कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश के जरिये किसी न किसी रूप में उपद्रव मचाया जाए। इस काम में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद मिली चीन से जो भारत की आजादी के समय से ही पूर्वोत्तर राज्यों के जरिये इस काम में जुटा है। इधर पाक परमाणु कार्यक्रम में भी चीन का सहयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है।

भारत से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार तो हासिल कर लिये, लेकिन तब भी वो अच्छी तरह जानता है कि भारत से टकराव की हालत में उसकी हार निश्चित है जबकि ठीक उसके विपरीत चीन से टक्कर मोल लेना भारत को महंगा पड़ सकता है। इन दो परिस्थितियों ने चीन और पाकिस्तान के बीच इस एक बिंदु पर सहमति बनी कि क्यों न पड़ोसी देशों को भारत का भय दिखाकर उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा की जाए, जिसका

**भारत का नेपाल से सहज रूप में रिश्ता बनता है। इसलिए उस स्थिति में भारत की चिंता स्वाभाविक है जब नेपाल ऐसे देशों को अपना हितैषी माने जो भारत के प्रतिद्वंद्वी हैं**

उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, सबके सब आ गए चक्कर में जिसका सबूत है कि आज ये सारे देश भारत विरोधी केन्द्र बने हुए हैं। हालांकि इस बीच म्यांमार और बांग्लादेश से संबंध बेहतर बनाने के भारत की ओर से पुरजोर कोशिश हुई है, जो सफल भी हो रही है।

लेकिन नेपाल में सरकारी और गैर सरकारी स्तर से चल रहे कई मामले भारत के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं जो भारत को नेपाल से अपने संबंध के विषय में नयी सोच अपनाने के लिए एक प्रकार से बाध्य कर रहे हैं। अब यह नेपाली नीति-निर्धारकों को तय करना है कि वो चीन को अपना ज्यादा मददगार मानते हैं या भारत को जिसकी नेपाल में रिश्तेदारी के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंध भी हैं। नेपाल का चीन की ओर मुखातिब होना निश्चित रूप से उसकी असुरक्षा की भावना से जुड़ा है।

1962 में भारत-चीन युद्ध में भारत की हार के बाद नेपाल को लगा कि चीन को ही ज्यादा भरोसेमंद माना जाए। भारत-नेपाल संबंधों का इतिहास बताता है कि वीरेन्द्र के पिता महाराज महेन्द्र के समय में चीन से संपर्क बढ़ाने और भारत से दूरी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ।

1962 की लड़ाई के बाद ही यह खुलकर सामने आ गया, जब नेपाल ने भारत के साथ सैनिक संबंध तोड़ लिए और वहां नेपाल की सुरक्षा के लिए रह रहे भारतीय सैनिकों को बोरिया बिस्तर समेटने को कह दिया। भारत से करीबी संबंध बनाने का श्रेय जाता है नेपाली कांग्रेस को, जिनके राजशाही के खिलाफ चलाये गए आंदोलन में भारत सहयोगी रहा। 1990 में जब वहां जनतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई तो सबसे पहले राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने राजमहल के इशारे पर नेपाली कांग्रेस में फूट डाली। इसके पीछे दो उद्देश्य काम कर रहे थे। एक तो यह कि देश में कोई राजनीतिक दल मजबूत न बनने पाए और ऐसी पार्टी सत्ता में न आ पाए जो भारत से ज्यादा दोस्ती का हिमायती हो।

बाद के वर्षों में राजशाही के खिलाफ खूनी आंदोलन चलाने वाले माओवादी कम्युनिस्टों ने इस काम में महारत हासिल कर ली जिनका भारत विरोध कई रूपों में सामने आ रहा है। 1976 से माओवादियों की सक्रियता बढ़ी है जब तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पहली बार पाकिस्तान गए और उसके बाद एमसीसी ने आईएसआई से सांठगांठ की।

अभी यह गठजोड़ नेपाल में भारतीय शैली की पढ़ाई वाले स्कूलों पर हमला करता है, मधेसिया कहलाने वाले भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाए हुए है और अलग गोरखालैंड राज्य की मांग मनवाने के लिए दार्जिलिंग में नये सिरे से हिंसात्मक आंदोलन चलाने वाले गोरखा मुक्ति आंदोलन के नेता छत्र सुब्बा के सहयोगियों को छापामार युद्धकला भी सिखाता है।

वास्तव में भारत को उसी समय नेपाल की नीयत का पता चल गया था जब पाक अफगान आतंकवादियों ने नेपाल की जमीन पर भारतीय विमान का अपहरण किया। आज उस समय नेपाल ने चीन से निकटता बढ़ानी शुरू की है, जब नेपाल तिब्बत सीमावर्ती गांवों में चीन की मदद से जगह-जगह एमसीसी ने हथियार प्रशिक्षण केन्द्र खोल रखे हैं जिनके भारत के उत्तर-पूर्व में सक्रिय उल्फा तथा नागा उग्रवादियों से ताल्लुकात हैं।